अध्याय- 5

5

लोकतंत्र की चुनौतियाँ

लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार में "लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है ।" भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा कर दी गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है । यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । नये विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में 71 करोड़ मतदाता है । पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि पिछले सौ वर्षों से दुनिया भर में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ । दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था नहीं है । कोई दूसरी शासन-प्रणाली इसकी प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने । लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है तथा एक आर्थिक आदर्श है ।

अब प्रश्न है कि हम सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे ?

क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखाओं में बँधकर कार्य करना चाहेंगे ?

लोकतंत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनपर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा । अलग-अलग देशों के सामने अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं । ये

> माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और उनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार का सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते हैं, जो वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं हो सकता । ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह होते हैं । भारत ने शासन-प्रणाली वही अपनाई है लेकिन यहाँ राष्ट्रपति रबर स्टांप नहीं है । नेपाल में यह बिल्कुल संभव नहीं है ।

चुनौतियाँ किसी साधारण समस्याओं जैसी नहीं हैं । हम साधारणतः उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्त्वपूर्ण तो है, लेकिन उनपर सफलता भी हासिल की जा सकती है । जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था नहीं है, उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है । उदाहरण के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के बाद शुरू हुआ लोकतांत्रिक प्रयोग सफलता एवं असफलता के बीच फँस गया है।

उत्तरी आयरलैंड जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटो की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया, चार साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभावों से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर है ।

प्रचंड सहित सभी माओवादी नेताओं को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में, और वह भी मिली–जूली सरकार में, अपनी इच्छा लादना संभव नहीं है ।

अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है । इसमें लोकतांत्रिक शासक के बुनियादी सिद्धांतों को सभी लोगों, सभी सामाजिक समारोहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना, शामिल है । स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार सम्यक बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियाँ हैं ।

नेपाल की संसद में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिसिस्ट, लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया । उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ । 240 साल पुराने राजशाही को खत्मकर लोकतांत्रिक देश बनाया । इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है ।

तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है । हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती विद्यमान है । इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुध ारना तथा मजबूत बनाना शामिल है ताकि लोगों के नियंत्रण में वृद्धि हो सके ।

वर्तमान समय में भारत में भी लोकतंत्र की चुनौतियाँ विकट रूप में विद्यमान है । भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है । इसमें शासन

का संचालन जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के तीन अंग हैं– कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है। अमेरिका का और ब्रिटेन की लोकतांत्रिक सफलता बहुत हद तक उनकी न्यायपालिका की सफलता है।

> अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिलटन ने कहा था कि "कार्यपालिका में उर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएँ हैं, जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इनमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से महँगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वॉर्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश–नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियाँ आदि कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनपर संजिदा बहस जरूरी है। देशों की अखंडता और एकता के लिए खतरा बन रही शक्तियों पर व्यापक परिचर्चा होनी चाहिए। यह खतरा केवल आतंकवादी गतिविधियों, पूर्वोतर के अलगाववादी या नक्सली गतिविधियों एवं अवैध शरणार्थियों से नहीं, बल्कि बढ़ते आर्थिक अपराधों से भी है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलन भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ ही हैं।

केंन्द और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं (शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल–मजदूरी एवं सामाजिक कुरुतियों इत्यादि) के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुँचती है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी समाधान खोजने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में लोकसभा और राज्य सभा के चुनाव में होनेवाले अन्धाधुन्ध चुनावी खर्च, उम्मीदवारों के टिकट वितरण और चुनावों की पारदर्शिता भी सम्मिलित है । वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टियाँ तथा गठबंधन की राजनीति भी महत्त्वपूर्ण, भूमिका निभाती हैं । स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी–छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाना जो दागी प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है ।

> पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से 265 सीटों पर विजय प्राप्त की गई । UPA द्वारा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद वह पूर्ण बहुमत के आँकड़े 272 से कुछ कम ही रह गया जबकि गठबंधन में शामिल काँग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 202 सीटें ही प्राप्त कर सकी । फिर भी उसे द्रमुक और तृणमूल काँग्रेस का दबाव सहना पड़ा ।

गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है । नई लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है । सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में इजाफा लोकतंत्र के लिए चुनौती है ।

> नाइजीरिया के चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान–बूझ कर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया । बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को भी गलत ढंग से जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया ।

> ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की संख्या 19.3 प्रतिशत, अमेरिका में 16.3 प्रतिशत, इटली में 16.01 प्रतिशत, आयरलैंड में 14.2 प्रतिशत तथा फ्रांस में 13.9 है ।

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएँ होती रही हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं में निरक्षता दूर करने, शिक्षा में आनेवाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

दी गई है । परिणाम यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से बढ़ती नजर आने लगी । 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से अधिक हो गई है । संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल अभी तक पारित नहीं हो सका है, लेकिन महिलाओं ने अपने दम पर भारत को विकसित देशों के करीब ला खड़ा किया है ।

आज की महिलाएँ राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं । खेतीबारी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक जा रही हैं । इसके बावजूद वे दोयम दर्जे की शिकार हैं । ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार ने नई पंचायती राजव्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किया है । गाँवों में आज जो महिलाएँ पंच और सरपंच चुनी जा रही हैं, उनमें ज्यादातर अपने परिवार के पुरुषों के प्रभाव में काम कर रही हैं । ऐसा देखा जा रहा है कि गाँवों की पंचायतों या नगर परिषदों में निर्वाचित महिला मुखिया के स्थान पर उसका पति/पुत्र अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है । यह अप्रत्यक्ष रूप से यह भारतीय लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है ।

अब तक हमने भारत के संदर्भ में लोकतंत्र की चुनौतियों को देखा । एक नजर बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों पर भी डाल कर देखें । भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित है । उसके बावजूद यहाँ क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर चुनौतियाँ मौजूद हैं । आज भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयाँ यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं । हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई उसके ही किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए । यह भारतीय लोकतंत्र की खामियों को दर्शाता है ।

> सत्तारूढ़ जद (यू) ने 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान यह कह दिया था कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी । इस बात को लेकर जद (यू) में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई थी ।

अब यह देखना है कि जद (यू) टिकट बँटवारे संबंधी इस उद्‌घोषित निर्णय पर टिकता है या परिवारवादियों के समक्ष घुटने टेक देता है । जातीय वोट बैंक बनाकर वर्षों तक चुनाव जीतने वाले कुछ नेता तथा राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान हैं । आगामी 2010 का बिहार विधानसभा का आम चुनाव यह बता देगा कि जातीय वोट बैंक की राजनीति कारगर रहेगी या नहीं । ऐसा देखा गया है कि जो नेता अपने लिए जातीय वोट बैंक का सुरक्षित किला बना लेते हैं वे सत्ता में आने के बाद आम लोगों के सामान्य विकास में कोई रुचि नहीं रखते हैं । वैसे नेतागण कुछ खास जातीय समूहों व व्यक्तियों के लिए ही सरकारी स्तर से सामूहिक व व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं । इस शैली की राजनीति से बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है । राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध, अफसरशाही, लूटतंत्र, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, प्राकृतिक आपदा, नारियों की खराब स्थिति, पंचायतों और प्रखंडों में फैला भ्रष्टाचार ये सभी बिहार में स्थापित लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं ।

© BSTBPC WEBCOPY NOT TO BE PUBLISHED

अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ

उदाहरण और संदर्भ	इस मामलें में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण
चिले : जनरल पिनोशे की सरकार चुनाव में हार गई, लेकिन अनेक संस्थाओं पर अभी भी सेना का कब्जा बरकरार है।	(उदाहरण) सभी सरकारी संस्थाओं पर नागरिक-नियंत्रण, पहला बहुदलीय चुनाव कराना, निर्वाचित नेताओं को स्वदेश बुलाना ।
पोलैंड : सोलिडरिटी की पहली सफलता के बाद सरकार ने सैनिक शासन लागू कर दिया और सोलिडरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया ।	
घाना : आजादी मिली और एनक्रूमा राष्ट्रपति चुने गए ।	

म्याँमार : 15 वर्षों से ज्यादा से सू की जनरबंद, सैनिक शासन को विश्व–स्तर पर मान्यता ।	
अंतरराष्ट्रीय संगठन : बची रह गई एकमात्र महाशक्ति अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं करता और एकतरफा फैसले करता है।	
मैक्सिको : पी० आर० आई० की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र	
चुनाव : पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धाँधली की शिकायत की ।	
चीन : कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है ।	
पाकिस्तान : जनरल मुर्शरफ जनमत संग्रह कराए और मतदाता सूची में गड़बडी के आरोप लगाए ।	
इराक : नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती; बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा ।	
दक्षिण अफ्रीका : मंडेला का सक्रिय राजनीति से सन्यास; उनके उत्तराधिकार मबेकी पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव ।	

अमेरिका, गुआंतानामी बे : संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं; अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार ।	
सऊदी अरब : महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों पर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं; धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं ।	
युगोस्लाविया : कोसोवो प्रांत में सर्व और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव ; यूगोस्लाविया बिखर गया।	
बेल्जियम : संवैधानिक सुधारों को एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट उनकी अधिक स्वायत्तता की माँग । **श्रीलंका :** सरकार और लिट्टे के बीच	
शांति वार्ता भंग, हिंसा फिर से भरकी । अमेरिका, नागरिक अधिकार : अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में । **उत्तरी आयरलैंड :** गृह–युद्ध समाप्त	
पर कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव ।	

© BSTBPC WEBCOPY .NOT TO BE PUBLISHED

नेपाल : संविधान सभा का चुनाव होने वाला है; तराई में असंतोष; माओवादियों ने हथियार नहीं सौंपे ।	
बोलिबिया : बल-संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने । बहुराष्ट्रीय कंपनियों में धमकी दी कि ... ? जले जायेंगे ।	

अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ

अब, जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें । नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है । पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियाँ को बताया था । आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं । इनके अलावा, भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक-एक उदाहरण दर्ज करें । अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट नहीं बैठती तो आप नयी श्रेणियाँ बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं ।

संवैधानिक बनावट	
लोकतांत्रिक अधिकार	
संस्थाओं का कामकाज	
चुनाव	
संघवाद विकेंद्रीकरण	
विविधता को समेटना	

राजनीतिक संगठन	
कोई अन्य श्रेणी	
कोई अन्य श्रेणी	

आइए, इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें । इस बार इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएँगे । इन सभी श्रेणियों के लिए कम-से-कम एक उदाहरण भारत से भी खोजें ।

आधार तैयार करने की चुनौतियाँ	
विस्तार की चुनौती	
लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती	

आइए, अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें । समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर गौर करें । इनमें से उन पाँच की सूची बनाइए जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए । यह सूची प्राथमिकता को भी बताने वाली होनी चाहिए । यानी आप जिस चुनौती को सबसे महत्त्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें । शेष को इसी क्रम के बाद में । ऐसी चुनौती का एक उदाहरण दें और बताएँ कि आपकी प्राथमिकता में उसे कोई खास जगह क्यों दी गई है ।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

प्राथमिकता	लोकतंत्र की चुनौती	उदाहरण	प्राथमिकता का कारण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

राजनीतिक सुधारों पर विचार

प्रत्येक चुनौतियों के साथ सुधार की संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं । हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें उनका समाधान कर पाना संभव लगता है । लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं । अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई एक ही तरीका नहीं अपना सकता है । हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं । लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो । कुछ महत्त्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर दिए जा सकते हैं । यहाँ तक कानून बनाकर राजनीतिक सुधारों की बात सोचना लुभावना हो सकता है लेकिन इसपर पाबंदी लगना भी आवश्यक है । सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे काम-काज को प्रौत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता है । राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यत: राजनीतिक कार्यकर्त्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिक द्वारा ही हो सकता है । कई बार कानूनी बदलाव के परिणाम एकदम उलटे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सख्ती से चुनाव

लड़ने पर रोक लगा दी, जिसके चलते अनेक लोग और महिलाएँ लोकतांत्रिक अवसर से बंचित हो गए, जबकि सरकार की ऐसी को मंशा नहीं थी ।

राजनीतिक कार्यकर्त्ता को अच्छे काम के लिए बढ़ावा देने के लिए कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है । सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं ।

सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है । ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है । लोकतांत्रिक सुधार मुख्यत: राजनीतिक दल ही करते हैं । अत: राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यत: लोकतांत्रिक कामकाज पर ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए ।

लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों की सफल होने की संभावना होती है ।

© BSTBPC WEB COPY, NOT TO BE PUBLISHED

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें ।

1. लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है
   (क) नागरिकों की उदासीनता पर
   (ख) नागरिकों की गैर-कानूनी कार्रवाई पर
   (ग) नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर
   (घ) नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर

2. 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी
   (क) 10 प्रतिशत (ख) 15 प्रतिशत
   (ग) 33 प्रतिशत (घ) 50 प्रतिशत

3. ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है'' यह कथन –

(क) अरस्तू (ख) अब्राहम लिंकन

(ग) रूसो (घ) ग्रीन

4. नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग

(क) 90 करोड़ (ख) 71 करोड़

(ग) 75 करोड़ (घ) 95 करोड़

5. क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ?

(क) अपने क्षेत्र से लगाव (ख) राष्ट्रहित

(ग) राष्ट्रीय एकता (घ) अलगाववाद

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ।

1. भारतीय लोकतंत्र .... लोकतंत्र है । (प्रतिनिध्यात्मक/एकात्मक)
2. न्यायपालिका में .... के प्रति निष्ठा होनी चाहिए । (सत्य/हिंसा)
3. भारतीय राजनीति में महिलाओं को .... प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। (33 प्रतिशत/15 प्रतिशत)
4. वर्तमान में नेपाल की शासन–प्रणाली .... है । (लोकतंत्रात्मक/राजतंत्र)
5. 15वीं लोकसभा चुनाव में UPA द्वारा ..... सीटों पर विजय प्राप्त की गई । (265/543)

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very -Short- Answer Questions)

1. लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है । कैसे ?
2. केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है?
3. परिवारवाद क्या है ?
4. आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें ।
5. सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे ?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions)

1. लोकतंत्र से क्या समझते हैं ?
2. गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है ?
3. नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है ? लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या-क्या बाधाएँ हैं ?
4. क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है ?
5. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है । कैसे ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. वर्त्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं ? विवेचना करें ।
2. बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है ?
3. परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है ?
4. क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं ?
5. न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे ? इसके सुधार के उपाय क्या है ?
6. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती हैं ? स्पष्ट करें ।

*

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED